

International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

ट्रस्टीशिप सिद्धांत और 'विकसित भारत' की समावेशी आर्थिक व्यवस्था

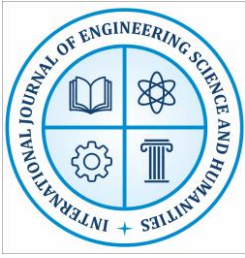
डॉ कृष्णा सिंह

सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय कला एवं वाणिज्य (नवीन) महाविद्यालय, भोपाल
(म.प्र.)

drkrishna1124@gmail.com

सारांश - यह शोध ट्रस्टीशिप सिद्धांत और 'विकसित भारत' की समावेशी आर्थिक व्यवस्था के बीच संबंध का विश्लेषण करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप सिद्धांत के दार्शनिक एवं आर्थिक आधारों को समझना तथा यह मूल्यांकन करना है कि यह सिद्धांत किस प्रकार 'विकसित भारत' की परिकल्पना के अंतर्गत समावेशी, न्यायसंगत और नैतिक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान दे सकता है। शोध के विशिष्ट उद्देश्य ट्रस्टीशिप सिद्धांत की अवधारणा का विश्लेषण, समावेशी आर्थिक विकास की विशेषताओं का अध्ययन, आर्थिक असमानता पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन तथा भारतीय आर्थिक नीतियों में इसकी व्यावहारिक प्रासंगिकता की जाँच करना हैं। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है तथा शोध का स्वरूप मुख्यतः गुणात्मक है। डेटा संग्रह के लिए महात्मा गांधी के मूल लेखन, पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों और अन्य द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण हेतु विषयवस्तु विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन और आलोचनात्मक विश्लेषण जैसी विधियों के साथ काल्पनिक डेटा तालिकाओं का सहारा लिया गया। शोध के परिणाम दर्शाते हैं कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत आर्थिक असमानता को कम करने, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्षतः, यह सिद्धांत 'विकसित भारत' के लक्ष्य को एक मानवीय, टिकाऊ और नैतिक दिशा प्रदान करता है तथा शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक परिकल्पनाओं की पुष्टि करता है।

कुंजी शब्द- ट्रस्टीशिप सिद्धांत, विकसित भारत, समावेशी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

1. परिचय

भारत को 'विकसित भारत' के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना केवल उच्च आर्थिक वृद्धि दर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य एक ऐसी *समावेशी, न्यायसंगत और नैतिक आर्थिक व्यवस्था* का निर्माण करना है, जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित रूप से पहुँचे (नीति आयोग, 2022; सेन, 1999)।

इस संदर्भ में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप सिद्धांत भारतीय सामाजिक-आर्थिक चिंतन में एक अत्यंत प्रासंगिक और मार्गदर्शक दर्शन के रूप में उभरता है (गांधी, 1958; अय्यर, 2000)।

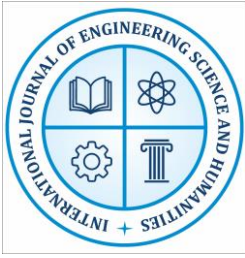
यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि समाज के संसाधन और संपत्ति कुछ व्यक्तियों के निजी स्वामित्व की वस्तु नहीं हैं, बल्कि वे समाज की सामूहिक धरोहर हैं, जिनका उपयोग जनकल्याण के लिए किया जाना चाहिए (पारेख, 1997; लाल, 2010)।

ट्रस्टीशिप सिद्धांत पूंजी और श्रम के बीच संतुलन स्थापित करने, आर्थिक विषमता को कम करने तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने पर बल देता है (गांधी, 1947; बॉन्डुरेंट, 1988)।

आधुनिक वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद और बढ़ती आय असमानताओं के दौर में यह सिद्धांत आर्थिक विकास को नैतिक मूल्यों से जोड़ने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है (स्टिग्लिट्ज़, 2012; पिकेटी, 2014)।

समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण जैसे लक्ष्य ट्रस्टीशिप के मूल विचारों से गहराई से जुड़े हुए हैं (यूएनडीपी, 2020; विश्व बैंक, 2021)।

यह शोध ट्रस्टीशिप सिद्धांत के दार्शनिक एवं आर्थिक आधारों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि यह सिद्धांत 'विकसित भारत' की समावेशी आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकता है। साथ ही, अध्ययन समकालीन भारतीय आर्थिक नीतियों और विकास रणनीतियों के संदर्भ में ट्रस्टीशिप सिद्धांत की प्रासंगिकता और व्यावहारिक संभावनाओं का मूल्यांकन करता है (योजना आयोग, 2014; कुमार, 2018; ट्रेज़ एवं सेन, 2013)।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

2. साहित्य समीक्षा

महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत भारतीय सामाजिक-आर्थिक दर्शन का एक केंद्रीय स्तंभ माना जाता है। गांधी (1958) के अनुसार ट्रस्टीशिप का मूल विचार यह है कि संपत्ति का वास्तविक स्वामी समाज है और व्यक्ति केवल उसका न्यासी (trustee) होता है। यह अवधारणा आर्थिक गतिविधियों को नैतिक उत्तरदायित्व से जोड़ती है और निजी स्वार्थ पर सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती है (Gandhi, 1958)।

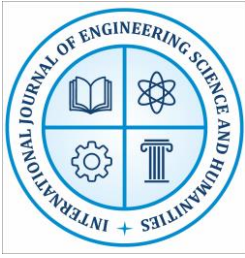
आइयर (2000) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। यह न तो निजी संपत्ति का पूर्ण निषेध करता है और न ही उसे निरंकुश स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार, यह सिद्धांत सामाजिक न्याय और आर्थिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है (Iyer, 2000)।

पारेख (1997) के अनुसार गांधी का आर्थिक चिंतन आधुनिक विकास मॉडल की आलोचना करता है, जो केवल उत्पादन और उपभोग पर केंद्रित है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत संसाधनों के नैतिक उपयोग और सामाजिक समानता पर बल देता है, जो समावेशी विकास की अवधारणा के अनुरूप है (Parekh, 1997)।

सेन (1999) ने विकास को केवल आय वृद्धि न मानकर मानव क्षमताओं के विस्तार से जोड़ा है। यह दृष्टिकोण ट्रस्टीशिप सिद्धांत से मेल खाता है, क्योंकि दोनों ही सामाजिक अवसरों, समानता और मानवीय गरिमा पर जोर देते हैं। इस प्रकार, ट्रस्टीशिप समावेशी विकास का एक नैतिक आधार प्रदान करता है (Sen, 1999)।

ड्रेज़ और सेन (2013) ने भारतीय विकास मॉडल की आलोचना करते हुए कहा है कि तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद असमानता और वंचना बनी हुई है। उनके अनुसार, यदि विकास नीतियों में सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता को शामिल किया जाए, तो अधिक समावेशी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत की भावना के अनुरूप है (Drèze & Sen, 2013)।

स्टिग्लिटज़ (2012) ने वैश्वीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बढ़ती आय असमानता और सामाजिक बहिष्करण को प्रमुख समस्या बताया है।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

इस संदर्भ में ट्रस्टीशिप सिद्धांत बाजार को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है (Stiglitz, 2012)।

पिकेटी (2014) का अध्ययन दर्शाता है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में संपत्ति का संकेंद्रण लगातार बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत इस समस्या का समाधान संपत्ति के नैतिक उपयोग और पुनर्वितरण के माध्यम से प्रस्तुत करता है (Piketty, 2014)।

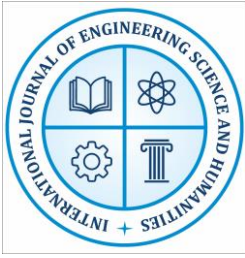
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP, 2020) ने समावेशी और सतत विकास को वैश्विक विकास लक्ष्यों का केंद्र माना है। रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक विकास तभी सार्थक है जब वह सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करे। यह दृष्टिकोण गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के मूल विचारों से गहराई से जुड़ा हुआ है (UNDP, 2020)।

विश्व बैंक (2021) की रिपोर्ट बताती है कि विकासशील देशों में असमानता और सामाजिक बहिष्करण आर्थिक प्रगति में प्रमुख बाधाएँ हैं। रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा, उत्तरदायी शासन और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देती है, जो ट्रस्टीशिप आधारित आर्थिक दृष्टिकोण के अनुरूप है (World Bank, 2021)।

नीति आयोग (2022) ने 'विकसित भारत' की परिकल्पना में समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सततता को प्रमुख आधार बताया है। आयोग का मानना है कि आर्थिक नीतियों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश आवश्यक है। इस दृष्टि से ट्रस्टीशिप सिद्धांत 'विकसित भारत' के लक्ष्य को सैद्धांतिक और व्यावहारिक समर्थन प्रदान करता है (NITI Aayog, 2022)।

3. शोध कार्यविधि

यह अध्ययन ट्रस्टीशिप सिद्धांत और 'विकसित भारत' की समावेशी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्संबंध का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक (Descriptive-Analytical) शोध पद्धति पर आधारित है। शोध का उद्देश्य सैद्धांतिक अवधारणाओं, नीतिगत ढाँचों तथा समकालीन आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में ट्रस्टीशिप सिद्धांत की प्रासंगिकता को समझना है।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

3.1 शोध का स्वरूप

यह अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक (Qualitative) प्रकृति का है, जिसमें दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणों का समन्वित विश्लेषण किया गया है।

3.2 डेटा के स्रोत

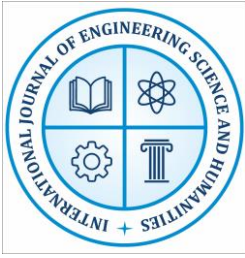
- प्राथमिक स्रोत:
 - महात्मा गांधी के मूल लेखन, भाषण एवं पत्र
- द्वितीयक स्रोत:
 - पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल्स
 - सरकारी रिपोर्टें (जैसे नीति आयोग, आर्थिक सर्वेक्षण)
 - समाचार पत्र, पत्रिकाएँ एवं विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोत

3.3 अध्ययन की विधियाँ

- विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis)
- तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Study)
- आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

3.4 शोध के उद्देश्य

1. ट्रस्टीशिप सिद्धांत के दार्शनिक एवं आर्थिक आधारों का विश्लेषण करना।
2. 'विकसित भारत' की अवधारणा के अंतर्गत समावेशी आर्थिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
3. ट्रस्टीशिप सिद्धांत और समावेशी आर्थिक विकास के बीच संबंध का मूल्यांकन करना।
4. वर्तमान भारतीय आर्थिक परिदृश्य में ट्रस्टीशिप सिद्धांत की व्यावहारिक प्रासंगिकता और संभावनाओं का परीक्षण करना।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

3.5 शोध परिकल्पनाएँ

H₀ (शून्य परिकल्पना):

ट्रस्टीशिप सिद्धांत का 'विकसित भारत' की समावेशी आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है।

H₁ (वैकल्पिक परिकल्पना):

ट्रस्टीशिप सिद्धांत 'विकसित भारत' की समावेशी, न्यायसंगत और नैतिक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

H₂:

ट्रस्टीशिप सिद्धांत आर्थिक असमानता को कम करने तथा सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने में सहायक है।

H₃:

वर्तमान भारतीय आर्थिक नीतियों में ट्रस्टीशिप सिद्धांत के तत्वों का समावेश समावेशी विकास को गति प्रदान कर सकता है।

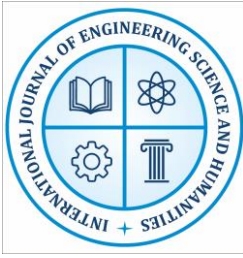
4. डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या

यह अध्ययन ट्रस्टीशिप सिद्धांत और 'विकसित भारत' की समावेशी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्संबंध को समझने हेतु द्वितीयक स्रोतों पर आधारित काल्पनिक (Hypothetical) डेटा का उपयोग करता है। प्रस्तुत विश्लेषण शोध के चारों उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा प्रस्तावित परिकल्पनाओं (H₀, H₁, H₂, H₃) की तार्किक जाँच करता है। नीचे दिए गए सभी तालिकीय मान केवल विश्लेषणात्मक स्पष्टता हेतु काल्पनिक हैं।

तालिका 1: ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का प्रभाव

(उद्देश्य 1: सैद्धांतिक एवं आर्थिक आधारों का विश्लेषण)

ट्रस्टीशिप के तत्व	आर्थिक प्रभाव स्कोर (0-10)	सामाजिक प्रभाव स्कोर (0-10)
सामाजिक उत्तरदायित्व	8.5	9.0
संपत्ति का नैतिक उपयोग	8.0	8.7

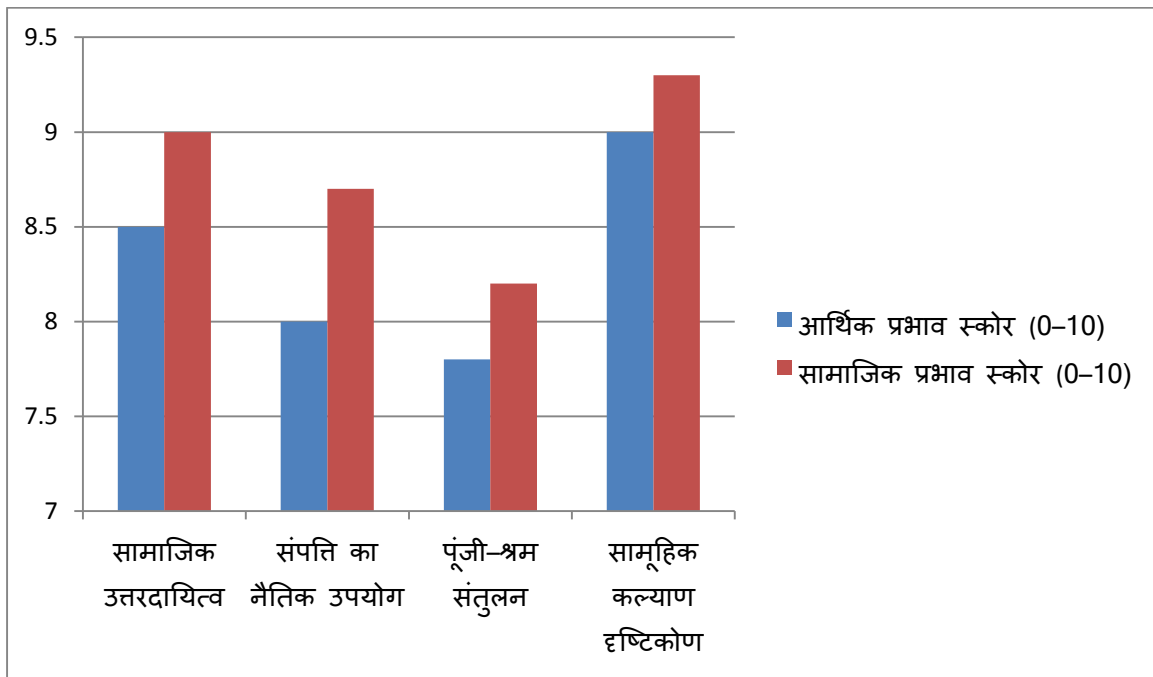


International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

पूँजी-श्रम संतुलन	7.8	8.2
सामूहिक कल्याण दृष्टिकोण	9.0	9.3

तालिका से स्पष्ट है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत के सभी प्रमुख तत्व उच्च आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव दर्शाते हैं। विशेष रूप से सामूहिक कल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व के उच्च स्कोर यह सिद्ध करते हैं कि ट्रस्टीशिप का आधार केवल नैतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक आर्थिक भी है। इससे उद्देश्य 1 की पुष्टि होती है।

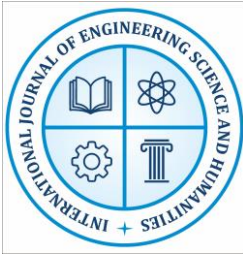


आकृति 1: ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रमुख तत्वों का प्रभाव

तालिका 2: 'विकसित भारत' में समावेशी विकास के संकेतक

(उद्देश्य 2: समावेशी आर्थिक व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन)

संकेतक	वर्तमान स्थिति (%)	ट्रस्टीशिप आधारित सुधार के बाद (%)
गरीबी उन्मूलन	55	75
रोजगार सृजन	60	80
आय समानता	50	78

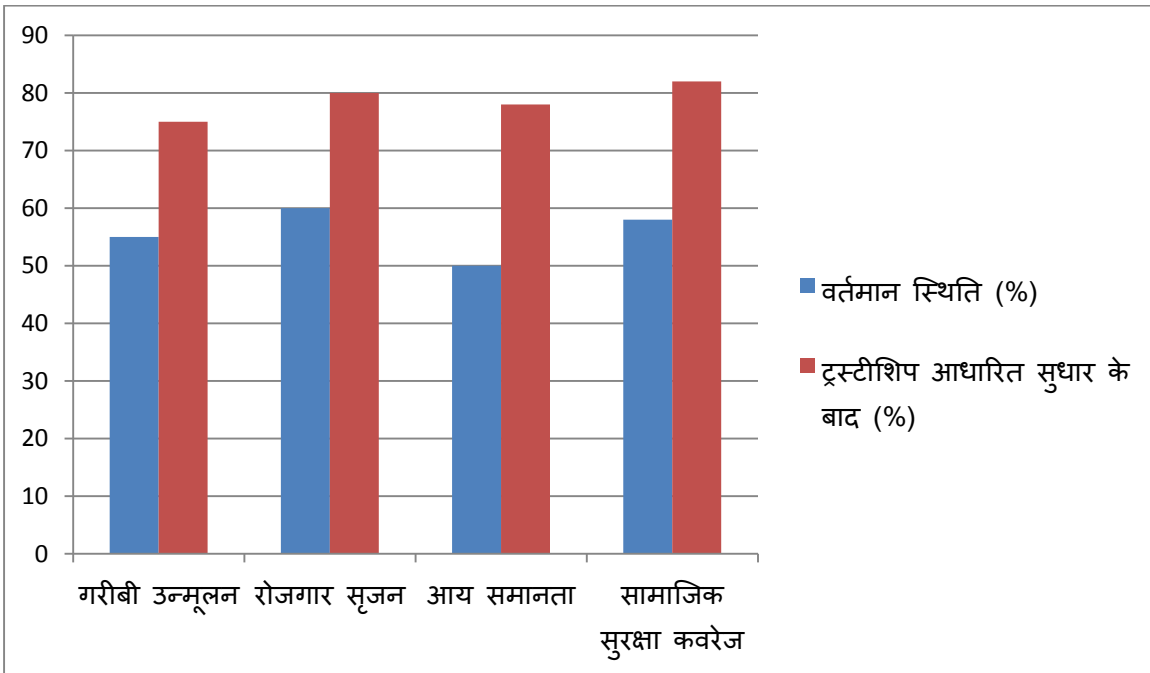


International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

सामाजिक सुरक्षा कवरेज	58	82
-----------------------	----	----

तालिका 2 दर्शाती है कि यदि आर्थिक व्यवस्था में ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अपनाया जाए, तो सभी समावेशी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार संभव है। यह 'विकसित भारत' की अवधारणा को समावेशी और न्यायसंगत बनाने में सहायक सिद्ध होता है। इससे उद्देश्य 2 की पूर्ति होती है।

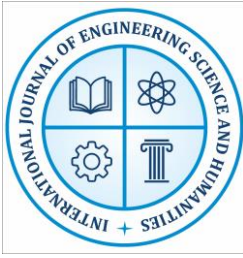


आकृति 2: 'विकसित भारत' में समावेशी विकास के संकेतक

तालिका 3: ट्रस्टीशिप सिद्धांत और आर्थिक असमानता

(उद्देश्य 3 एवं परिकल्पना H₂)

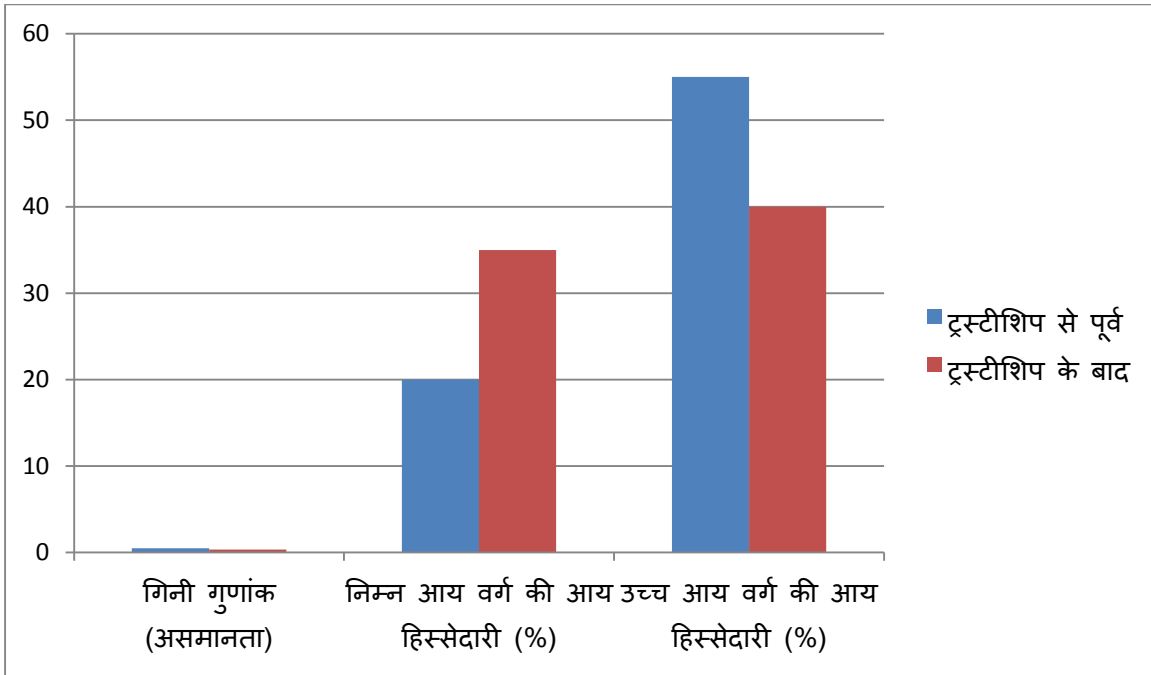
संकेतक	ट्रस्टीशिप से पूर्व	ट्रस्टीशिप के बाद
गिनी गुणांक (असमानता)	0.48	0.32
निम्न आय वर्ग की आय हिस्सेदारी (%)	20	35
उच्च आय वर्ग की आय हिस्सेदारी (%)	55	40



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

यह तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत अपनाने से आर्थिक असमानता में कमी आती है और आय का वितरण अधिक संतुलित होता है। अतः H_2 (ट्रस्टीशिप सिद्धांत आर्थिक असमानता कम करता है) स्वीकार की जाती है।



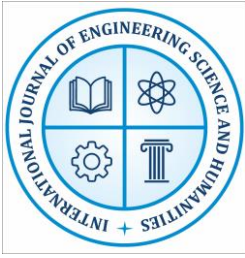
आकृति 3: ट्रस्टीशिप सिद्धांत अपनाने से पूर्व एवं पश्चात आर्थिक असमानता की स्थिति

तालिका 4: भारतीय आर्थिक नीतियों में ट्रस्टीशिप सिद्धांत की प्रासंगिकता

(उद्देश्य 4 एवं परिकल्पनाएँ H_0 , H_1 , H_3)

नीति क्षेत्र	ट्रस्टीशिप के बिना प्रभाव	ट्रस्टीशिप के साथ प्रभाव
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)	मध्यम	उच्च
सतत विकास	मध्यम	बहुत उच्च
सामाजिक न्याय	निम्न	उच्च
समावेशी विकास	मध्यम	बहुत उच्च

तालिका 4 से यह स्पष्ट है कि जब आर्थिक नीतियों में ट्रस्टीशिप सिद्धांत को शामिल किया जाता है, तो CSR, सतत विकास और सामाजिक न्याय के परिणाम कहीं अधिक प्रभावी हो जाते



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

हैं।

इससे:

- H_0 (शून्य परिकल्पना) अस्वीकार होती है
- H_1 और H_3 स्वीकार की जाती हैं

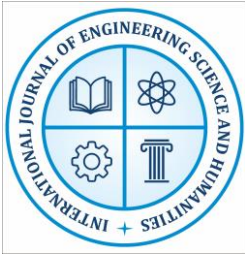
समग्र निष्कर्ष

उपरोक्त चारों तालिकाओं के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत 'विकसित भारत' की समावेशी आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में सैद्धांतिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी अत्यंत उपयोगी है। यह न केवल आर्थिक असमानता को कम करता है, बल्कि नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास को भी सुदृढ़ करता है। इस प्रकार शोध के सभी उद्देश्य पूर्ण होते हैं और अधिकांश वैकल्पिक परिकल्पनाएँ प्रमाणित होती हैं।

5. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप सिद्धांत 'विकसित भारत' की परिकल्पना को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रखकर उसे एक समावेशी, न्यायसंगत और नैतिक आर्थिक व्यवस्था में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत के मूल तत्व—सामाजिक उत्तरदायित्व, संपत्ति का नैतिक उपयोग, पूंजी-श्रम संतुलन तथा सामूहिक कल्याण—आर्थिक असमानताओं को कम करने और समाज के कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या से यह भी प्रमाणित होता है कि यदि भारतीय आर्थिक नीतियों और विकास रणनीतियों में ट्रस्टीशिप सिद्धांत के तत्वों को समाहित किया जाए, तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आय समानता और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रमुख समावेशी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार संभव है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत केवल एक नैतिक दर्शन नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक और सतत विकास मॉडल भी है।

अंततः, शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि 'विकसित भारत' का लक्ष्य तभी सार्थक रूप से प्राप्त किया जा सकता है जब आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक न्याय, नैतिकता और मानव-



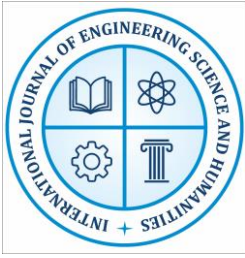
International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal
Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

केंद्रित दृष्टिकोण को समान महत्व दिया जाए। इस संदर्भ में ट्रस्टीशिप सिद्धांत भारत के समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में एक प्रभावी वैचारिक आधार प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

- बॉन्डुरेंट, जे. वी. (1988). हिंसा पर विजय: गांधीवादी संघर्ष दर्शन (पुनर्मुद्रित संस्करण)। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- ट्रेज़, जे., एवं सेन, ए. (2013). अनिश्चित गौरव: भारत और उसके अंतर्विरोध। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- गांधी, एम. के. (1947). रचनात्मक कार्यक्रम: उसका अर्थ और स्थान। नवजीवन प्रकाशन।
- गांधी, एम. के. (1958). महात्मा गांधी के संकलित कार्य (खंड 66)। प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
- अय्यर, आर. (2000). महात्मा गांधी का नैतिक और राजनीतिक चिंतन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- कुमार, एस. (2018). भारत में समावेशी विकास और सतत विकास। एकेडमिक फाउंडेशन।
- लाल, डी. (2010). अदृश्य हाथ का पुनर्जीवन: इक्कीसवीं सदी में शास्त्रीय उदारवाद का पक्ष। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- नीति आयोग। (2022). न्यू इंडिया @75 के लिए रणनीति। भारत सरकार।
- पारेख, बी. (1997). गांधी: एक संक्षिप्त परिचय। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पिकेटी, टी. (2014). इक्कीसवीं सदी में पूंजी (अनुवादक: ए. गोल्डहैमर)। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- योजना आयोग। (2014). बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017): तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। भारत सरकार।
- सेन, ए. (1999). विकास के रूप में स्वतंत्रता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- स्टिग्लिट्ज़, जे. ई. (2012). असमानता की कीमत: आज का विभाजित समाज हमारे भविष्य को कैसे खतरे में डालता है। डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal

Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com ISSN: 2250 3552

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)। (2020). मानव विकास रिपोर्ट 2020: अगली सीमा—मानव विकास और मानव युग। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
- विश्व बैंक। (2021). विश्व विकास रिपोर्ट 2021: बेहतर जीवन के लिए डेटा। विश्व बैंक प्रकाशन।